to many units in Bihar using coal as a principal fuel. Its attitude in financing projects has been sympathetic and any project which involves adoption of new techniques or processes receives its close attention.

Rise in production cost of Cotton Textile Industry

9866. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether production cost in the Cotton Textile Industry is expected to rise further during 1974-75; and

(b) if so, the remedial steps proposed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): (a) and (b). The costs of production of cotton cloth depends on the prices of cotton, stores and fuel and wages and D.A., etc. Production costs in the Cotton Textile Industry during 1974-75 will very according to these factors.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी कार्यवाही समिति

9867. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों के उत्पादन में वृद्धि के लिए योजना आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक कार्यसमिति बनाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सुझाव पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). योजना आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में सरकारी उद्यमों के संबंध में एक कार्य समिति की स्थापना की गयी है। इस समिति को सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के उपायों का पता लगाने का काम सौंपा गया है। समिति द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों का संबंध नीचे बताये गए कामों से है।

(1) प्रबंध कार्य को पुख्ता बनाना;

(2) संयंत्र और निगम स्तर पर संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन;

(3) संयंत्र प्रबन्ध में सुधार;

(4) अनुरक्षण के काम का विकेन्द्रीकरण;

(5) संतुलनकारी और अड़चनों को दूर करने से संबंधित कुछ सुविधाओं की व्यवस्था;

(6) सामग्री प्रबंध कार्मिकों को प्रोत्साहन प्रदान करने, उत्पादन-आयोजन और नियंत्रण के कार्य में सुधार;

(7) कार्यसंचालन की समय पर समीक्षा और नियंत्रण की उपयुक्त व्यवस्था करना;

(8) बेहतर निगम आयोजन ;

(9) गवेषणा और विकास कार्यों तथा अन्य तकनीकी सेवाओं को मजबूत बनाना;

(10) बिक्री तथा विपणन के कार्य में सुधार;

(11) औद्योगिक संबंधों में सुधार; और

(12) काम को कई पारियों में चलाना।

इनमें से अधिकांश सिफारिशों को सरकार ने मंजूर कर लिया है और वे क्रियान्वयन के अलग-अलग दौरों में हैं।